NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

New Indian Express, Hyderabad, 16/07/2026
Page No: 4, Size: 14.08cm × 7.38cm

CUSTODIAL TORTURE

NHRC orders ₹50,000 compensation

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Hyderabad

THE National Human Rights Commission (NHRC) has directed the state government to pay ₹50,000 as compensation to the family of Sai Siddhu, a tribal youth who died allegedly following custodial torture in Nalgonda district in September 2025.

The NHRC said that despite sufficient opportunity, neither the chief secretary nor the DGP responded to its show-cause notice. It therefore confirmed its earlier recommendation and ordered the compensation.

According to the complaint, Sai Siddhu, an auto driver from Kothapet Thanda, was picked up by Wadapally police from his home on the night of September 9, 2025, allegedly subjected to caste-based abuse and third-degree torture, and suffered a fractured leg.

His wife, Bathimila Dina, was also allegedly abused when she intervened. The complaint alleged violations of constitutional safeguards, provisions of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act and Supreme Court guidelines on custodial violence.

After the Telangana government failed to respond to its show-cause notice issued on April 25, the NHRC directed the state to pay compensation to the victim's family.

Dainik Jagran, Patna, 16/07/2026
Page No: 6, Size: 62.10cm × 51.17cm

पटना समेत 10 जिलों में सबसे अधिक मामले 15 से 18 वर्ष की किशोरियां निशाने पर, पांच साल में 65 हजार से अधिक प्राथमिकी

बिहार से गुम हो रहीं बेटियां, 42 प्रतिशत मामलों में मानव तस्करी

नेपाल सीमा से जुड़े जिले और पटना सबसे बड़ा हाटस्पाट

- पटना (शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक मामले), मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया,पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), भागलपुर, कटिहार, बेतिया (पश्चिम चंपारण), औरंगाबाद, दरभंगा

किशोरियों पर कुदृष्टि जमाने वालों के विरुद्ध समाज को खड़ा होना होगा। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यदि कोई बेटी लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं है तो हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। दैनिक जागरण इस मामले को उचित फोरम तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, ताकि कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

7091595959

गुम हो रहीं बेटियां

शुभम कुमार • जागरण

पटना : पाटलिपुत्र की रहने वाली एक महिला की 18 वर्षीय बेटी बीते दस दिनों से लापता है। दीघा गई थी, आज तक नहीं लौटी है। मोबाइल भी बंद है। राजधानी का ही एक और मामला। आलमगंज थाना क्षेत्र से 13 जुलाई को दो नाबालिग बहनें एक साथ लापता हो गईं। पुलिस की एक टीम उन्हें ढूंढ़ने में लगाई गई है।

ये इक्का-दुक्का मामले नहीं हैं। पूरे बिहार से लड़कियों और महिलाओं के लापता होने के पीछे संगठित गिरोह और मानव तस्करी का नेटवर्क है, जिस पर लगाम नहीं लगाने पर स्थिति और भयावह हो सकती है। सारण में एक आर्केस्ट्रा से 14 जुलाई को तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। इसी जिले की मांझी नगर पंचायत क्षेत्र की दो सगी बहनें चार माह पहले लापता हुईं, जिनमें एक का शव महाराष्ट्र के सांगली जिले में मिला है। बड़ी बहन पुलिस संरक्षण में है। फेसबुक पर एक युवक से संपर्क होने के बाद दोनों घर से निकल गई थीं। अहम मुद्दा यही है कि कम उम्र की इन लड़कियों को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रमित किया जाता है, वे कुछ समझ नहीं पातीं। झांसे में आ जाती हैं या गायब हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही मामला कुछ माह पहले आया था, जब गोपालगंज से नाबालिग बरामद की गई थीं।

यह सीधे मानव तस्करी का मामला है। आधिकारिक आंकड़े भी बता रहे हैं कि 42 प्रतिशत मामलों में मानव तस्करों का हाथ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के आंकड़े बता रहे कि राज्य में बेटियों के लापता होने की सबसे बड़ी और प्रमुख वजह मानव तस्करी है। बिहार में हर दिन औसतन 30 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा 15 से 18 वर्ष की किशोरियों का है। कुल लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या लगभग 77 प्रतिशत है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विभिन्न जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार कुल दर्ज मामलों में से अकेले 42 प्रतिशत मामलों के पीछे सीधे तौर पर मानव तस्करों का हाथ है। गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के समेकित आंकड़ों के अनुसार, बिहार में बीते पांच वर्षों में गुमशुदगी और अपहरण के मामलों का ग्राफ लगातार ऊपर गया है, लेकिन उस अनुपात में बरामदगी दर केवल 53.3 प्रतिशत के आसपास रुकी हुई है। पटना में ही हर साल 700 से 800 लड़कियों और महिलाओं के गायब होने की रिपोर्ट है।

बिहार में लापता बच्चों (18 वर्ष से कम) की स्थिति (एनसीआरबी एवं गृह मंत्रालय रिपोर्ट)

वर्ष	पिछले वर्षों के लंबित मामले	एफआइआर	कुल लापता बच्चे	बरामदगी	साल के अंत में लंबित मामले
2020	5,105	6,540	11,645	6,210	5,435
2021	5,435	7,120	12,555	6,840	5,715
2022	5715	7,850	13,565	7,110	6,455
2023	6,455	8,420	14,875	7,650	7,225
2024	7,225	9,110	16,335	8,120	8,215

बिहार में गायब महिलाओं (18 वर्ष से अधिक) का रिकार्ड प्रतिशत में

वर्ष	प्राथमिकी	बरामद की गईं महिलाएं	अनसुलझे मामलों का प्रतिशत
2020	10,840	5,910	45.4
2021	11,620	6,230	46.3
2022	12,450	6,780	45.5
2023	13,616	7,150	47.4
2024	14,280	7,420	48.0

केवल नाबालिग लड़कियां (18 वर्ष से कम)

वर्ष	गायब नाबालिग लड़कियां	बरामद/ट्रेस की गईं	वर्षांत तक लापता (लंबित सहित)	दैनिक औसत
2021	3,870	4,442	5,366	10 से 11 लड़कियां
2022	5,204	4,935	5,635	14 लड़कियां
2023	4,466	5,527	4,574	12 लड़कियां

(नोट : बरामदगी के आंकड़ों में पहले के भी मामले हैं।)

रेस्क्यू के लिए बनाई गई हैं टीमें, होती है छापेमारी

जागरण संवाददाता, पटना : पटना की सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लिया जाता है। नाबालिग लड़कियों के मामले में कई परेशानियां होती हैं। उनके पास मोबाइल नहीं होता है, माता-पिता को कोई जानकारी नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में पाया जाता है कि लड़कियां प्रेम प्रसंग, बेहतर भविष्य और नौकरी का प्रलोभन में फंस जाती हैं। अगर लड़का सही है तो दूसरे राज्यों से उसका पता चल जाता है। कई बार लड़कियों को बेच दिया जाता है। लापता-गुमशुदगी के मामलों के लिए एसओपी है। एक एप है, जिस पर पुलिस द्वारा तस्वीर के साथ पूरा विवरण डाला जाता है। इस एप से पूरे देश भर की पुलिस के पास इसकी जानकारी चली जाती है। इसके अलावा जंक्शन, स्थानीय थाना व कई राज्यों के डीजीपी को पत्र भी लिखा जाता है। इसके लिए बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं। लगातार छापेमारी और रेस्क्यू किया जाता है।

सारण जिले से गायब लड़की का शव महाराष्ट्र के सांगली में मिला आर्केस्ट्रा से छुड़ाई गई

क्या हैं कारण

- **मानव तस्करी (42 प्रतिशत मामले)** : ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों की लड़कियों को बेहतर जिंदगी, महानगरों में अच्छी नौकरी या शादी का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है। तस्कर इन्हें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मुंबई जैसे राज्यों में ले जाकर बाल श्रम, देह व्यापार में धकेल देते हैं। जबरन शादी भी करा देते हैं।
- **इंटरनेट मीडिया व प्रेम-प्रसंग (28 प्रतिशत मामले)** : इंस्टाग्राम, फेसबुक और आनलाइन गेमिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण फर्जी पहचान बनाकर किशोरियों को बहलाने-फुसलाने के मामले तेजी से बढ़े हैं।
- **पारिवारिक कलह व घरेलू विवाद (18 प्रतिशत मामले)** : घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और बाल विवाह के सामाजिक दबाव से तंग आकर भी लड़कियां घर छोड़ देती हैं।
- **आर्थिक मजबूरी व प्रलोभन (12 प्रतिशत मामले)** : गरीबी का फायदा उठाकर स्थानीय बिचौलियों द्वारा महानगरों में घरेलू काम दिलाने के बहाने लड़कियों को बाहर ले जाया जाता है।

Source: https://www.deccanchronicle.com/southern-states/andhra-pradesh/ysrc-alleges-custodial-death-cover-up-police-deny-charge-1971197

YSRC Alleges Custodial Death Cover-Up; Police Deny Charge

Kakani also criticised the state government, saying the transfer of police personnel alone would not ensure justice. He said the YSRC, under the leadership of Y.S. Jagan Mohan Reddy, would continue its agitation until justice was delivered to Yedukondalu's family.

Nellore: Former minister and YSRC Nellore district president Dr Kakani Govardhan Reddy on Wednesday alleged that police were attempting to cover up the alleged custodial death of Yedukondalu, a Dalit resident of Cherukumudi village in Manubolu mandal, and demanded action against those responsible.

Accompanied by MLC Meriga Muralidhar, Kakani visited Gudur Government Hospital, where he met the victim's family and inspected the body. The bereaved family appealed for justice, and Kakani assured them of the party's support.

Addressing the media, Kakani alleged that Yedukondalu had been illegally detained for nearly three days in connection with a theft case and subjected to third-degree torture by Manubolu SI Hanif and other police personnel, resulting in his death. He claimed police were attempting to portray the incident as a suicide despite visible injury marks on the body.

He further alleged that police delayed shifting the victim to hospital, attempted to manipulate evidence and failed to follow due legal procedures. Kakani also accused police of extorting gold from suspects and their families during the investigation, claiming that only a fraction of the recovered property had been officially accounted for.

The former minister demanded a transparent inquiry, videography of all proceedings, a post-mortem under expert supervision and action against the police personnel allegedly involved. He said the YSRC would submit complaints to the National Human Rights Commission and the National Commission for Scheduled Castes, alleging serious human rights violations.

Kakani also criticised the state government, saying the transfer of police personnel alone would not ensure justice. He said the YSRC, under the leadership of Y.S. Jagan Mohan Reddy, would continue its agitation until justice was delivered to Yedukondalu's family.

Meanwhile, police strongly denied the custodial death allegation, maintaining that Yedukondalu was not in custody when he died.

According to police, three suspects - Riyaz, Yedukondalu and Prasad were detained in connection with a gold-snatching case reported on July 8. During questioning, they allegedly confessed to stealing 20 agricultural pump sets, which were subsequently recovered.

Police said the three were served notices under Section 35 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and released on the night of July 12. CCTV footage allegedly showed them on the national highway later that night and near a wine shop in the early hours of July 13. Police said they had no contact with them on July 13 or 14.

On the evening of July 14, police found Yedukondalu in a semi-conscious state near the Kanupuru canal. With the help of villagers, he was shifted to hospital, where doctors declared him dead.

Superintendent of Police Dr Ajitha Vejendla dismissed the torture allegations as baseless and said a medical team was conducting the post-mortem at Gudur Government Hospital. She said a comprehensive investigation had been launched based on the family's complaint.

Source: https://kathmandupost.com/national/2026/07/15/majid-ansari-discharged-from-hospital-after-five-days-questions-legal-basis-of-police-detention

Majid Ansari discharged from hospital after five days, questions legal basis of police detention

Ansari was among three Gen Z campaigners detained after reaching the centre to express support for the affected families.

Majid Ansari, a Gen Z activist who was discharged from hospital after five days on Wednesday, questions the legal basis of his detention by police. He was detained after an altercation with police during a solidarity visit to a holding centre for displaced squatters in Kirtipur on Saturday. According to him, police officers have yet to explain the legal basis for detaining him or provide any arrest documents.

Ansari, a LLB student at Nepal Law Campus, was admitted to Tribhuvan University Teaching Hospital in Maharajgunj after he was injured during Saturday's incident at the Kirtipur holding centre, where displaced squatters had been relocated following flooding.

Ansari was among three Gen Z campaigners detained after reaching the centre to express support for the affected families. Police released Sarisma Thapa and Nelson Ghatani later the same evening after recording their statements, but Ansari has remained under medical care.

Speaking from his hospital bed, Ansari said police had repeatedly asked him to sign a document despite never showing him an arrest warrant.

"I have not received any arrest papers. Police officers keep coming and pressuring me to sign a document, but I have refused," he said.

Ansari alleged that police officers assaulted him while taking him into a police van after he demanded to see an arrest warrant. He claimed police abused him verbally and told him not to engage in politics as a student.

"I was grabbed from behind and beaten. My vision became blurred and I could not see properly for some time," he said, adding that he still suffers from body pain.

According to Ansari, an officer later told him he remained in police custody. He questioned how that could be the case when he had never been formally arrested under the law.

Deputy Superintendent of Police Shiva Kumar Budhathoki, chief at Kirtipur Police Circle, previously said Ansari had been detained for obstructing police while they were carrying out their duties.

According to Thapa, the three detainees were initially held inside the Kirtipur police office after the National Human Rights Commission was informed about the incident. They were later taken to Kirtipur Hospital for medical examinations.

She said hospital staff initially declined Ansari's request for an X-ray, but the examination was conducted after police approval. Doctors later referred him to Tribhuvan University Teaching Hospital after concluding that further scans were necessary.

Ansari also alleged that police officers remained inside his hospital cabin for several days before lawyers asked them to wait outside.

Kathmandu Police spokesperson Pawan Kumar Bhattarai, however, denied that Ansari was under arrest or investigation. "He was not arrested. Police intervened when two sides clashed at the holding centre gate, and he was injured in the process," said Bhattarai. "After he complained of injuries, he was taken to Kirtipur Hospital and later referred to the Teaching Hospital after doctors suspected a fracture."

The incident comes amid growing scrutiny of police handling of demonstrations linked to recent evictions of

informal settlements in the Kathmandu valley. Rights activists have repeatedly urged authorities to respect due legal process and the constitutional right to peaceful protest while maintaining public order.

Source: https://www.onmanorama.com/news/kerala/2026/07/15/tvm-woman-s-death-post-delivery-nhrc-orders-inquiry-seeks-action-taken-report.html

TVM woman's death post-delivery: NHRC orders inquiry, seeks action taken report

Thiruvananthapuram: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) in connection with the death of a 26-year-old woman who died while undergoing treatment for complications following childbirth at a government hospital in Thiruvananthapuram.
The deceased, JR Shivapriya, a native of Pettah, died on November 9, 2025. Following her death, her family approached the NHRC alleging medical negligence, claiming that her repeated complaints of abdominal pain and subsequent symptoms of infection after delivery were not addressed promptly by hospital authorities.
According to the complaint, Shivapriya later developed post-partum sepsis and was shifted to the intensive care unit for advanced treatment, but succumbed to the infection. The family also alleged that the government's internal inquiry failed to identify the source of the infection or adequately assess whether the standard of medical care provided was appropriate. They contended that the incident amounted to a violation of her Right to Life under Article 21 of the Constitution.
Taking cognisance of the petition, the Commission observed that the allegations raised serious human rights concerns. It directed the Principal of Government Medical College, Thiruvananthapuram, to conduct an inquiry and submit a report within two weeks. The Commission also sought an Action Taken Report within the same period.
According to the petition, Shivapriya visited Fort Taluk Hospital on October 19, 2025, after noticing reduced fetal movements. As scanning facilities were unavailable, she was referred to Sree Avittam Thirunal (SAT) Hospital, where she delivered a baby boy through normal delivery on October 22 and was discharged two days later.
The family alleged that she complained of abdominal pain before discharge, but was told it was likely caused by gastric discomfort. Although she was later given medication, she developed a fever and chills soon after returning home. She was readmitted to SAT Hospital on October 26 with an infection, following which her stitches were reopened. She was shifted to the Medical College's Super Speciality Medical ICU on October 27 and placed on ventilator support on October 30. She died on November 9.
The petition further claimed that a scan conducted a day before her death revealed a blood clot, but she died shortly afterwards.
The family alleged that the hospital failed to provide adequate post-natal care and argued that timely intervention when she first reported abdominal pain could have prevented her death. They also questioned the credibility of the hospital's internal inquiry, alleging that it failed to determine the source of the infection and did not independently assess the quality of treatment provided.
Seeking an independent medical board to investigate the case, the petition stated that the existing inquiry did not meet the standards of a fair and impartial probe. It also argued that the death had deprived the newborn of maternal care, protection and emotional security, further underscoring the need for an independent investigation.
Advocate Sekhar G Thampi appeared on behalf of Shivapriya's family.

Source: https://www.livelaw.in/amp/news-updates/nhrc-andhra-pradesh-police-missing-girls-tracing-state-541449

NHRC Directs Probe Into Missing Girls Cases In Andhra Pradesh, Seeks Details Of Police Protocol

The National Human Rights Commission has sought information from the Andhra Pradesh police about the number of children who went missing between 2022-2025, the policies followed to trace them and steps proposed to be taken by the police for tracing girls who have not yet been rescued.

The order was passed on a plea by Y Balachander Reddy who had pointed to a news report dated 24.01.2024 stating that over 3000 girls went missing in Andhra Pradesh and that only very few were traced. As per the report, more than 8 girls go missing every day, and 1 out of them remains untraced

The news report also mentioned that, 474 missing and untraced girls were reported from previous years, contributing to a total of 3,592 reported missing girls in the State. Of them, 3,221 girls were recovered or traced. However, 371 girls remained unrecovered or untraced.

The Commission had on 06.03.2024 issued notices to the Chief Secretary and DGP, Andhra Pradesh calling upon them to submit their response.

As per a report submitted by the State's Chief Secretary dated 07.01.2025, 61 children were missing in 2022, 74 children went missing in 2023 and 223 children who went missing in 2024 could not be traced. The commission however noted that the report was silent about the steps taken for tracing the remaining.

Transmitting the file to NHRC's Investigation Division, the commission directed its DG(I) to convene a Video Conference with the Directior General of Police along with an officer from Anti Human Trafficking Unit, if there is one in the State to find out:

(i) how many children went missing during 2022 to 2025?

(ii) how many children were traced?

(iii) what happened to the children who were traced?

(iv) whether the rescued children were rehabilitated with the family and kept in home, rehabilitated or not?

(v) the standard protocol which the police is following for tracing the remaining victims and

(vi) the steps proposed to be taken by the police for tracing the girls who are not yet rescued.

Source: https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/nhrc-orders-50000-compensation-in-nalgonda-custodial-torture-case-1971126

NHRC Orders ₹50,000 Compensation in Nalgonda Custodial Torture Case

Commission cites police, medical lapses; seeks report from Nalgonda Collector

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Telangana government to pay ₹50,000 as compensation to Sai Siddu in an alleged custodial torture case in Nalgonda district.

The case stems from a complaint alleging that Siddu, a tribal youth and auto driver, was picked up by Wadapally police in September 2025 and subjected to third-degree torture, resulting in injuries. While a police inquiry did not conclusively prove torture, the NHRC noted that medical evidence suggested otherwise.

The Commission flagged discrepancies between two medical reports--one from a hospital in Miryalaguda stating there were no visible injuries, and another from Nalgonda hospital recording swelling and inflammation in the victim’s feet. It observed that there was a “preponderance of probability” indicating custodial torture.

The NHRC also pointed to prima facie negligence by Sub-Inspector A. Srikanth Reddy and the duty medical officer who conducted the initial examination. Despite issuing a show-cause notice, the Commission said no response was received from state authorities.

Taking serious note, the NHRC confirmed compensation and directed the Nalgonda Collector to submit an inquiry report, warning of further action for non-compliance.

Source: https://www.outlookindia.com/national/delhi-residents-seek-nhrc-recognition-of-extreme-heat-as-a-human-rights-issue

Delhi Residents Seek NHRC Recognition Of Extreme Heat As A Human Rights Issue

Citizen-maintained “Heat Registries” document the impact of rising temperatures on health, livelihoods and dignity, as residents seek stronger legal recognition and funding for Heat Action Plans
On 14 July, A group of Delhi residents has approached the National Human Rights Commission (NHRC), urging it to recognise extreme heat as a human rights issue. Along with a formal representation submitted to NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian, residents presented citizen-maintained “Heat Registries” documenting the impacts of extreme heat on their health, livelihoods, income and dignity.
Maintained since May 2026 under Greenpeace India’s Delhi Rising campaign, the Heat Registries contain handwritten testimonies from nearly 40 households across Sunder Nagri, CR Park, Dwarka and Jamia Nagar, as well as informal workers including street vendors, gig workers, home-based workers, students and elderly residents. The diaries are supported by medical records, electricity bills and income documents, providing evidence of the financial and physical burden of prolonged heat exposure.
What are Heat Registries?
Since May 2026, residents have been maintaining weekly handwritten diaries to document their lived experiences of extreme heat. The diaries record how prolonged hot and humid conditions affect their daily lives and are supported by evidence such as medical bills, electricity bills and income records.
The initiative aims to capture the human and economic impacts of heat that are often missed by official statistics. Although Delhi is not currently under an official heatwave, participants say persistent heat and humidity continue to disrupt their health, work and household expenses.
According to the India Meteorological Department (IMD), Delhi’s maximum temperatures are currently between 36°C and 38°C, while minimum temperatures range from 26°C to 28°C. The IMD has forecast a slight increase in temperatures over the next two to three days, followed by a 2–3°C decline.
The submission argues that even without an official heatwave declaration, persistent heat, humidity and warm nights have resulted in sleeplessness, illness, reduced productivity, increased household expenses and loss of income, particularly among outdoor workers and vulnerable communities.
The representation states that these impacts amount to violations of fundamental rights protected under the Constitution.
It cites Article 21, which guarantees the right to life, along with Supreme Court judgments including Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal, Francis Coralie Mullin v. UT of Delhi, Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, M.C. Mehta v. Kamal Nath (2000) and M.K. Ranjitsinh v. Union of India (2024), which recognised protection against the adverse effects of climate change as part of the fundamental rights guaranteed under Articles 14 and 21.
Why is it being called a human rights issue?
Residents argue that prolonged extreme heat is not merely a weather event but a rights issue. They say it undermines their right to life, right to health, right to livelihood, and right to live with dignity, as persistent hot and humid conditions continue to affect their daily lives, incomes and overall well-being.
They say vulnerable communities are experiencing these rights violations through lost income, worsening health conditions and inadequate access to protection from extreme heat.
The letter also refers to the NHRC’s advisory issued on April 28, 2026, urging 21 states and the National Capital Territory of Delhi to take advance measures to protect vulnerable populations from heatwaves. It further cites the

2025 advisory opinions of the International Court of Justice and the Inter-American Court of Human Rights, both of which affirm that protecting people from climate change impacts is a binding human rights obligation.

Residents argue that although Heat Action Plans have been developed by many states and cities, they continue to suffer from inadequate financial support. According to the submission, measures such as cooling shelters, shaded public spaces, drinking water facilities, healthcare preparedness and early warning systems cannot be effectively implemented without dedicated funding.

What are the residents demanding?

The submission urges the NHRC to recognise extreme heat as a human rights issue and accept the Heat Registries as evidence of the harm caused by prolonged heat exposure. It also calls for dedicated funding for Heat Action Plans and supports the Sixteenth Finance Commission's recommendation to classify heatwaves as a nationally recognised disaster.

Speaking on behalf of informal workers, Mohit Valecha, National Coordinator of the Indian Hawkers Alliance, said extreme heat has significantly reduced the earnings of street vendors while exposing them to serious health risks without adequate social protection.

Aakiz Farooq, Senior Climate and Energy Campaigner at Greenpeace India, said the testimonies show that extreme heat affects people’s health, livelihoods, income and dignity, making it a human rights issue rather than only an environmental concern.

Climate law researcher Arpitha Kodiveri, Assistant Professor of Political Science at Vassar College, said legal systems across the world are increasingly recognising the need to address heatwaves through a human rights framework, including access to cooling, water, shelter and livelihood protections.

The residents have urged the Commission to place the Heat Registries on record and recommend stronger legal protections and financial support for Heat Action Plans, arguing that the growing impacts of extreme heat require recognition as a human rights concern rather than solely a climate or weather issue.

Source:
https://www.purvanchaltimes.in/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%
%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-
%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक रिटायर्ड IPS उपेंद्र सिंह बघेल ने चकिया थाने का किया औचक निरीक्षण, मुकदमों की ली जानकारी

चंदौली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के विशेष प्रतिवेदक रिटायर्ड IPS उपेंद्र सिंह बघेल ने चकिया थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में दर्ज विभिन्न मुकदमों की प्रगति, अभिलेखों तथा पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करते हुए जांच में पूरा सहयोग किया। स्पेशल रैपोर्टियर ने थाने की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और मानवाधिकार संबंधी मामलों में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया। निरीक्षण शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।

Source: https://www.jagran.com/bihar/patna-city-bihar-over-30-girls-women-vanish-daily-trafficking-rises-40307878.html

नौकरी, शादी और बेहतर जिंदगी का झांसा... बिहार से हर दिन गायब हो जाती हैं 30 बेटियां

बिहार में प्रतिदिन 30 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं, जिनमें 15-18 वर्ष की किशोरियां अधिक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मानव तस्करी इसका एक प्रमुख कारण है।

शुभम कुमार, पटना। बिहार में लड़कियों और महिलाओं के अचानक लापता होने के पीछे सक्रिय संगठित गिरोहों और मानव तस्करी के नेटवर्क का एक चिंताजनक पहलू सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सख्ती के बाद सामने आए आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं।

गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हर दिन औसतन 30 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं।

15 से 18 वर्ष की किशोरियां तस्करों के निशाने पर

लापता होने वालों में बड़ी संख्या 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों की है। कुल लापता बच्चों में लड़कियों की हिस्सेदारी लगभग 77 प्रतिशत बताई गई है।

विभिन्न जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, दर्ज मामलों में करीब 42 प्रतिशत मामलों के पीछे मानव तस्करी की भूमिका पाई गई है, जो अन्य कारणों की तुलना में सबसे अधिक है।

पांच वर्षों में 65 हजार से अधिक मामले दर्ज

गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में पिछले पांच वर्षों के दौरान गुमशुदगी और अपहरण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि, इसी अवधि में पुलिस की बरामदगी दर लगभग 53.3 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। पटना जिले में ही हर वर्ष 700 से 800 लड़कियां और महिलाएं लापता होने के मामले सामने आते हैं।

मानव तस्करी बनी सबसे बड़ा कारण

विशेषज्ञों के अनुसार ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को बेहतर जीवन, नौकरी या शादी का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है।

इसके बाद उन्हें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मुंबई जैसे राज्यों में ले जाकर शोषण और जबरन श्रम जैसे अपराधों में धकेले जाने के मामले सामने आते रहे हैं।

इंटरनेट और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले भी बढ़े

लगभग 28 प्रतिशत मामलों में इंटरनेट मीडिया और प्रेम-प्रसंग अहम कारण बनकर सामने आए हैं। फर्जी पहचान और ऑनलाइन संपर्क के जरिए किशोरियों को बहलाने-फुसलाने के मामले बढ़े हैं।

इसके अलावा पारिवारिक विवाद, घरेलू तनाव और सामाजिक दबाव भी कई मामलों में घर छोड़ने की वजह बनते हैं।

आर्थिक मजबूरी और प्रलोभन का भी असर

करीब 12 प्रतिशत मामलों में आर्थिक तंगी और रोजगार के प्रलोभन को कारण माना गया है। कई बार स्थानीय बिचौलिये घरेलू काम या नौकरी का लालच देकर लड़कियों को दूसरे राज्यों में ले जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और सतर्कता बढ़ाकर ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है।

पटना समेत 10 जिले सबसे अधिक प्रभावित

राज्य में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कटिहार, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद और दरभंगा ऐसे जिले हैं, जहां इस तरह के मामलों की संख्या अधिक है।

नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में भी मानव तस्करी के नेटवर्क की सक्रियता को लेकर एजेंसियां लगातार सतर्क हैं।

नाबालिग लड़कियों के मामलों को गंभीरता से ले रही पुलिस

सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। कई मामलों में लड़कियां बेहतर भविष्य, नौकरी या अन्य प्रलोभनों के कारण फंस जाती हैं।

उन्होंने बताया कि गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की जानकारी एक विशेष एप पर अपलोड की जाती है, जिससे देशभर की पुलिस इकाइयों तक सूचना पहुंच जाती है।

हाल की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

पाटलिपुत्र की रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती पिछले कई दिनों से लापता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है। वहीं आलमगंज क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला भी सामने आया है।

पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और संबंधित टीमों द्वारा लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

Source:
https://www.bhaskar.com/amp/g/local/bihar/muzaffarpur/news/cbi-seeks-report-on-compensation-and-rehabilitation-of-victims-dbp-138454389.html

बालिका गृह कांड:सीबीआई ने पीड़िताओं के मुआवजा व पुनर्वास की रिपोर्ट मांगी

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में पीड़िताओं को दिए गए मुआवजे और उनके पुनर्वास की वर्तमान स्थिति को लेकर सीबीआई ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, पटना की ओर से डीएम को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सीबीआई के अपर पुलिस अधीक्षक एवं जांच अधिकारी पवन कुमार श्रीवास्तव ने जारी पत्र में बताया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल 30 जून को बालिका गृह कांड से जुड़े आरोपितों की आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि पीड़िताओं को ट्रायल कोर्ट से निर्धारित मुआवजा मिला है या नहीं। साथ ही बताया जाए कि पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुआवजा भुगतान की स्थिति और यदि पुनर्वास की कोई योजना लागू की गई है तो उसकी विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन उपलब्ध कराए। इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

सीबीआई ने अपने पत्र में इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है, ताकि न्यायालय के आदेश का समय पर पालन सुनिश्चित किया जा सके। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का खुलासा हुआ था। इसके बाद 31 मई 2018 को समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने मुजफ्फरपुर में महिला थाने में एफआईआर कराई गई थी।

49 पीड़िताओं को मिल चुका है मुआवजा बिहार सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं के मुआवजा भुगतान से संबंधित रिपोर्ट पूर्व में सौंप चुकी है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि 49 पीड़िताओं को तीन से नौ लाख रुपए तक की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पुलिस व सीबीआई के बाद 29 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को लेकर केस दर्ज किया था। मानवाधिकार आयोग ने पीड़िताओं को मुआवजा देने की अनुशंसा कर रिपोर्ट मांगी थी। दूसरी ओर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने भी मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस पूरे केस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था।

इन्हें मिली थी सजा ब्रजेश ठाकुर (संरक्षक), इंदु कुमारी (अधीक्षिका), मीनू देवी (हाउस मदर), मंजू देवी (काउंसलर), चंदा देवी (हाउस मदर), नेहा कुमारी (नर्स), किरण कुमारी (हेल्पर), हेमा मसीह (प्रोबेशनरी अधिकारी), रवि रोशन (निलंबित सीपीओ- बाल संरक्षण पदाधिकारी), विकास कुमार (सीडब्ल्यूसी - बाल कल्याण समिति सदस्य), रोजी रानी (तत्कालीन सहायक निदेशक), विजय कुमार तिवारी (ब्रजेश का ड्राइवर), गुड्डू कुमार (रसोईया), कृष्णा कुमार राम (सफाईकर्मी), रामानुज ठाकुर (गेटकीपर), साहिस्ता परवीन उर्फ मधु (ब्रजेश की करीबी), अश्विनी कुमार (कथित डॉक्टर), दिलीप वर्मा (सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष), रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Online News, 16/07/2026

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-rescue-operation-against-human-trafficking-in-bihar-three-girls-freed-201784131441690.amp.html

आर्केस्ट्रा से तीन नाबालिग लड़कियां मुक्त, एक गिरफ्तार

पेज तीन की लीड इस दौरान एक आरोपित संचालकों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई सीनियर एसपी विनीत कुमार के निर्देश पर महिला थाना अध्यक्ष व टीम ने किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के...
पेज तीन की लीड आवाज दो अभियान के तहत लगातार जारी है पुलिस की सख्त कार्रवाई नेपाल और बिहार की लड़कियां मुक्त कराई गई छपरा, हमारे संवाददाता। महिलाओं और किशोरियों के शोषण के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत सारण पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित आर्केस्ट्रा समूहों पर छापेमारी कर 3 लड़कियों को मुक्त कराया। इस दौरान एक आरोपित संचालकों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई सीनियर एसपी विनीत कुमार के निर्देश पर महिला थाना अध्यक्ष व टीम ने किया।
महिला थाना की कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के पत्र के आलोक में गठित विशेष टीम ने नगरा थाना क्षेत्र में विधिवत घेराबंदी कर छापेमारी की। जांच के दौरान तीन नाबालिग लड़कियां बरामद की गईं, जिन्हें कथित रूप से जबरन प्रताड़ित कर आर्केस्ट्रा में नृत्य करवाया जा रहा था। इस संबंध में महिला थाना कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों में मंटू गिरि कटिया थाना क्षेत्र के गोपालगंज जिला का रहने वाला बताया जाता है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अन्य संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में महिला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी के साथ नगरा थाना अध्यक्ष के पदाधिकारी व कर्मी, एएचटीयू सारण के प्रभारी विशाल आनंद तथा मिशन मुक्ति फाउंडेशन के सदस्य शामिल थे। पूरी कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से की गई। उल्लेखनीय है कि सारण जिले में मई 2023 से अब तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुल 409 लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया जा चुका है। इस अवधि में कांड दर्ज कर 138 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। सारण पुलिस द्वारा महिलाओं के शोषण के खिलाफ 'आवाज दो' अभियान चलाया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी महिलाओं या किशोरियों के साथ जबरन शोषण या प्रताड़ना की सूचना मिले तो हेल्पलाइन नंबर 9031600191 पर तत्काल जानकारी दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। --- देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल छपरा, हमारे संवाददाता। सारण पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिनटोलिया गांव निवासी अनूप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राम पुकार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में अपराधियों, शराब कारोबारियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अवैध हथियार रखने वालों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। -

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
15.07.2026	Times Now Navbharat	15:20	Punjab Human Rights Organization के चेयरमैन का बड़ा बयान ! -सतलुज फ़िल्म विवाद पर मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा, "... लोगों ने उस पुलिस अफ़सर के बारे में पता करना शुरू किया जिसे उम्रकैद की सज़ा हुई थी और उन्हें पता चला कि उसे जेल से रिहा कर दिया गया है... उसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके रिहा किया गया था... हमारी मांग है कि उसे फिर से गिरफ़्तार किया जाए और अपनी उम्रकैद की सज़ा पूरी करने के लिए जेल वापस भेजा जाए..."	11:21 Min	Breaking News	Abc	
15.07.2026	IBC24	11:20	Bus Viral Video: बस में ठूंस-ठूंस कर भरे गए बच्चे। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान.	02:15 Min	Breaking News	Abc	
15.07.2026	Times Now	18:30	Muzaffarabad March' Today: Protests In PoK Escalate As Fight For 'Azadi' Begins -Large-scale protests have erupted in Pakistan-occupied Kashmir, with demonstrators accusing the Pakistani government and military of human rights violations and demanding basic rights. The unrest has drawn international attention, while India has criticized Pakistan's handling of the situation and expressed concern over reports of violence against protesters.	05:59 Min	Breaking News	Abc	
15.07.2026	Tv9 Kannada	19:00	Chikkamagaluru Shocker: Parents Accused Of Selling Their Own Daughter To Africa For Prostitution	02:59 Min	Breaking News	Abc	

15.07.2026	TV9 Bangla	14:30	Kasba Crime News: Illicit activities at a Kasba hotel—did the Trinamool remain silent while a former TMC councillor raised the issue?	03:10 Min	Breaking News	Abc	
15.07.2026	Times Now	19:00	Tamil Nadu Horror: 11 Arrested Over Custodial Death Of Specially-Abled Undertrial -The Tamil Nadu custodial death clash has taken a major turn with the arrest of eight prison inmates, taking the total number of arrests to 11, including three prison officials. The case relates to the death of specially abled undertrial prisoner who allegedly suffered multiple injuries while lodged in the District Prison.	02:51 Min	Breaking News	Nishant	
15.07.2026	India Today	15:00	Custodial torture death sparks serious questions once again in Tamil Nadu, TVK govt promises action.	18:18 Min	Breaking News	Abc	
15.07.2026	Times Now	14:20	Tamil Nadu Custodial Death Case: 8 Prison Inmates Arrested As Probe Into Jail Death Deepens -The investigation into the alleged custodial death of a 34-year-old disabled prisoner in Tamil Nadu has taken a significant turn, with eight prison inmates arrested as part of the ongoing probe. Earlier, three prison officials were arrested in connection with the case. The victim's family has alleged that he was subjected to torture while in custody, claims that are now under investigation.	02:16 Min	News	Abc	

15.07.2026	CNN-News18	18:20	Tamil Nadu Custodial Death News | L. Murugan Demands Murder Case Against Cops -A custodial death case in Nagercoil, Tamil Nadu, has triggered a major political controversy after Union Minister L. Murugan demanded that a murder case be registered against the accused police personnel in the death of Sabarivarma, a differently-abled youth. Addressing the issue, Murugan alleged that custodial deaths continue under the DMK government and called for stringent legal action against those responsible. The case has intensified the political debate over police accountability, custodial violence, and law and order in Tamil Nadu. The state government, police authorities, and political parties have responded as demands for a transparent investigation and justice continue to grow.	03:36 Min	Breaking News		
15.07.2026	NDTV Rajasthan	17:00	Bharatpur News: Dalit युवक की मौत पर भरतपुर में MP Sanjana Jatav का हल्लाबोल!	04:10 Min	Breaking News	Abc	
15.07.2026	TV9 Bharatvarsh	18:00	Delhi Police Operation Chakra Updates: 'ऑपरेशन चक्र' में 72 घंटे के अंदर 30 वाहन चोर गिरफ्तार	00:36 Min	Breaking News	Abc	

15.07.2026	ETV Bharat Rajasthan	17:20	Nagaur Police Operation: संदिग्ध विदेशी महिलाओं के मिलने के बाद, 12 होटल-गेस्ट हाउस खंगाले -कुचामन में होटल से संदिग्ध विदेशी महिलाओं के मिलने के मामले के बाद नागौर जिले में पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए शहर के कई होटलों और गेस्ट हाउसों पर एक साथ छापेमारी की. पुलिस, डीएसटी और क्यूआरटी की संयुक्त टीमों ने मंगलवार को करीब चार घंटे तक शहर के विभिन्न इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है.	01:03 Min	News	Abc	